RAJYA SABHA

Monday, the 28th July, 1986/6 Saravana, 1908 (Saka)

The House met at eleven of the Clock. Mr. Chairman in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रिहन्द सुपर ताप बिजली परियोजना

*141. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की लागत वाले रिहन्द सुपर ताप बिजली घर के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस बारे में हस्तक्षेप करे ;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने का निर्धारित कार्यक्रम क्या है ;

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ) रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा ब्रिटिश सहायता से स्थापित की जा रही है । परियोजना पर कार्य 500 मेगावाट की पहली यूनिट को अक्तूबर, 1987 में चालू किए जाने के लक्ष्य से चल रहा है, जबकि इसे जून, 1987 में चालू करने का कार्यक्रम था । पिछड़ने का मुख्य कारण मैसर्स नार्दर्न इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की ओर से परियोजना के प्रबंध संबंधी संसाधनों को जुटाने में विलम्ब तथा डिजाइन और इंजीनियरी कार्यों आदि को पूरा करने में विलम्ब होना है । परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित कराने के लिये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मैसर्स नार्दर्न इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के साथ समुचित सम्पर्क बनाए हुये हैं । सम्बन्धित ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से परस्पर कार्यवाही करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भारत सरकार भी परियोजना की मानीटरिंग कर रहे हैं ।

श्रीमती रत्न कुमारी : सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी द्वारा दिये गए स्टेटमेंट को देखा । नार्दर्न इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की ओर से इस कार्य में विलम्ब किया जा रहा है । यह राष्ट्र को बड़ा भारी नुकसान है । ऐसे बांधों में हजारों लोगों को काम मिलता है और हमारे देश की बेकारी की समस्या के हल में भी मदद मिलती है । सिंचाई की सुविधा होने से उपज बढ़ती है । इसके अलावा और भी कई लाभ जो इन योजनाओं से देश को मिलते हैं । क्या सरकार इस कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने के लिये नार्दर्न इंजीनयरिंग इंडस्ट्रीज को बाध्य करेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय, मैं माननीय सदस्या की बात से सहमत हूँ कि इस कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिये था और यह कार्य शीघ्र हो जाता तो इससे लोगों को काम मिलता, सिंचाई की सुविधा बढ़ती । कार्य प्रारम्भ हो गया है और प्रयास किया जा रहा है कि इसको शीघ्र समाप्त किया जाय ।

श्रीमती रत्न कुमारी : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने अपने विद्युत सचिव को हाल में विशेष रूप से यू०के० भेजा था बातचीत करने के लिये, यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हां, भारत सरकार ने पावर सचिव को 85 में भी भेजा था । जब मालूम हुआ कि विलम्ब हो

रहा है तो कारणों के मुद्दों को गहराई से समझने का प्रयास किया गया । अपनी यात्रा के दौरान वे वहां एन०ई०आई० के अधिकारियों से मिले । जो विलम्ब इस साल का हुआ उसको जल्दी से जल्दी कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में बात हुई इसके अतिरिक्त इस साल भी हमारे सचिव भेजे गये थे । भारत सरकार की ओर से उन्होंने चिन्ता प्रकट की कि जल्दी से जल्दी कार्य किया जाय । उसके उपरांत यह हुआ है कि जो कार्य टल गया था, '88 में समाप्त होना था वह '87 के अन्त तक पूर कर लिया जाएगा ।

श्री वसन्त साठे : मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ । अभी हमारे जो सचिव गये थे और उच्च स्तर पर बात हुई उसमें उन्होंने यह माना है कि हम अक्तूबर तक इसको पूरा करेंगे जिससे विलम्ब और भी कम हो जायेगा । चार महीने में हो जायेगा । अक्तूबर तक हो जायेगा, ऐसा उन्होंने माना है

MR. CHAIRMAN: Question No. 142.

Proposal for a venture with Pepsi Cola

*142. SHRI SURESH KALMADI:† SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Punjab Agro has applied for a tie-up with Pepsi Cola of U.S.A.;

(b) if so, what are the details of the collaboration venture, indicating the details of the technology to be imported, the items to be imported under the deal and the items and products to be exported by the resultant Company;

(c) how far the above imports are consistent with the import replenishment scheme; and

(d) whether the Company would be allowed to use foreign trade marks for the goods to be sold by them in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (d) M/s. Punjab Agro Industries Corporation limited have submitted an application for approval for manufacture of various Processed Foods in financial participation with one of the Tata Companies and M/s Pepsico Incorporated of U. S. A. The application is still to be considered by Government. The practice has been that the details of pending applications are not given out until the Government have taken a decision thereon.

SHRI SURESH KALMADI: Sir, I don't think that the Government wants to give details. And we, as Members of Parliament, are entitled, I think, to know whether Pepsicola is being brought into this country through the backdoor. Last year also, there was a proposal to have Papsicola in this country... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Jagesh Desai, if you interrupt, you will lose your chance.

SHRI SURESH KALMADI: Why is he getting excited?

MR. CHAIRMAN: You please address me. I am taking care of it. (*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE: Don't appear as if... (*Interruptions*)

SHRI SURESH KALMADI: Sir, there was a talk earlier of import substitution. But now we see the policy of the Government is just import, import Sir, the pepsi proposal was shot down last time and again now it is coming back. I do not know whether this technology is needed for this country. Isn't our soft drink industry already standing on its own feet?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Suresh Kalmadi